

जदयू ने भाजपा को चुनौती/धमकी दी कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें अन्यथा ...

जदयू की अप्रत्यक्ष धमकी यह है कि अगर चुनाव के नतीजों तक का इन्तजार करेगी भाजपा तो उस समय तो सभी स्वतंत्र होंगे नई परिस्थितियों में नए समीकरण ढूंढने के लिये

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर की खामोशी बुधवार को उस समय और गहरा गई, जब जनता दल (यूनाइटेड) जेडीयू ने अपने बड़े सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे।

जेडीयू नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाशिये पर धकेलने और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान जैसे अन्य सहयोगियों को टिकट वितरण में बढ़ावा देने की सुनियोजित कोशिश कर रही है।

पार्टी के सूत्रों ने बताया कि हालांकि जेडीयू ने यह मांग औपचारिक रूप से

- यह उल्लेखनीय है कि जदयू ने यह धमकी देने के लिए शायद राजनीतिक कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता नहीं चुना है।
- पर जदयू के खेमे में इस मुद्दे पर कई सप्ताह से बहस छिड़ी हुई है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से काफी अरसे से नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है।
- यह भी महसूस किया जा रहा है कि भाजपा में काफी हिचकिचाहट है नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बारे में।
- जदयू के कार्यकर्ता और नेता यह मानते हैं कि भाजपा का प्रयत्न है कि एनडीए के अन्य छोटे घटकों को, नीतीश को कमजोर करके पनपाया जाये।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाई, लेकिन भाजपा के बढ़ते दबदबे को लेकर पार्टी के भीतर कई हफ्तों से यह चर्चा चल रही थी। ताज़ा विवाद उस समय भड़का, जब भाजपा नीतीश कुमार को बिहार चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री पद का निर्विवाद चेहरा घोषित करने की अनिच्छुक नज़र आई।

जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी और

प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में कहा, “भाजपा यह तय नहीं कर सकती कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे लिए यह सवाल बेमानी है, क्योंकि हम कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार ही राज्य के निर्विवाद नेता हैं। अपने संन्यास या उत्तराधिकारी के बारे में फैसला केवल वही करेंगे।”

नीरज कुमार के ये बयान इस बात

की ओर इशारा करते हैं कि जेडीयू में भाजपा की हाल की चुनावी रणनीतियों को लेकर नाराज़गी बढ़ रही है, जिन्हें नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की छोटी पार्टियों से नज़दीकी और टिकट वितरण पर उसके नियंत्रण ने जेडीयू नेताओं में असंतोष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भजन गायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया

पटना, 15 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने आज 12 उम्मीदवारों की

- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें मैथिली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है।

दूसरी सूची जारी की। सूची के अनुसार, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर का प्रत्याशी बनाया गया है। मैथिली ठाकुर कल ही भाजपा में शामिल हुई हैं। बक्सर से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वांगचुक की पत्नी ने “हेबियस कॉर्पस” याचिका में संशोधन किया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता गीतांजलि जे. अंगमो को अपने पति सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एन एस ए) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली “हेबियस कॉर्पस” (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) में संशोधन करने की अनुमति दे दी।

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंबोलिया की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर, बुधवार को तय की है।

दो दिन पहले केन्द्र सरकार ने अंगमो को वांगचुक की गिरफ्तारी के आधार (ग्राउन्ड्स ऑफ डिटेन्शन) उपलब्ध कराए थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अंगमो की ओर से पेश हुए, ने अदालत से याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, ताकि सरकार द्वारा दिए गए गिरफ्तारी के आधारों को उचित रूप से चुनौती दी जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वांगचुक को

श्रीलंका की प्र.मंत्री आज भारत में

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसुर्या गुरुवार को तीन दिन की भारत यात्रा आयेंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भारतीय

- श्रीलंका की प्र.मंत्री डॉ. हरिणी अमरसुर्या तीन दिन के लिए भारत आयी हैं। पद ग्रहण के बाद वे पहली बार भारत आयी हैं।

नेताओं से मुलाकात करेंगी और उनके साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री यहां एक निजी टेलीविजन चैनल और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी। शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रही डॉ. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यह संशोधन वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने समझाकर करवाया

- सिब्बल ने कहा कि वांगचुक ने अपनी हिरासत के सम्बंध में कुछ नोट्स बनाए थे जो वे अपने वकील को देना चाहते थे पर सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी।
- कपिल सिब्बल का तर्क था कि वांगचुक को ये नोट्स अपने वकील को देने का अधिकार है और इन नोट्स से केस मजबूत होगा।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोट्स शेयर किए जाने पर सहमति दी पर कहा कि इन नोट्स से केस में देरी होती है तो उसका जिम्मेवार सरकार को नहीं ठहराया जाना चाहिए।

अपने नोट्स पत्नी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, “उन्होंने (वांगचुक) अपनी गिरफ्तारी को लेकर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें वे अपने वकील तक पहुंचाना चाहते थे। जो भी नोट्स वे तैयार करते हैं, उन्हें अपने वकील की सहायता लेने का अधिकार है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि

वे नोट्स वकील तक पहुंच सकें।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उन्हें नोट्स याचिकाकर्ता के साथ साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने में हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिक्स ट्रंप की अनिद्रा का भारी कारण क्यों बनता जा रहा है

ट्रंप जितने जोर शोर से टैरिफ की धमकियां देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेनदेन के लिये डॉलर को ही माध्यम बनाना चाहते हैं, डॉलर उतना ही कमज़ोर होता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने अंदाज़ में लौट आए हैं। ब्रिक्स समूह के खिलाफ उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वह “डॉलर पर बहुत मजबूत” हैं और “जो भी देश डॉलर में लेन-देन करना चाहता है, उसे उन देशों पर बहुत मिलेगी, जो ऐसा नहीं करते।” यह इस बात का संकेत है कि ब्रिक्स समूह की बढ़ती ताकत और प्रभाव को लेकर ट्रंप चिंतित है।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने दुनिया को यही संदेश दिया। उन्होंने कहा, “जो भी ब्रिक्स में रहना चाहता है, वह रहे, लेकिन हम उसके देश पर टैरिफ लगाएंगे। सब बाहर निकल गए हैं, सारे देश ब्रिक्स छोड़ रहे हैं।”

एक स्तर पर ट्रंप के ये बयान उनकी जानी-पहचानी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें वे व्यापारिक दबाव और टैरिफ को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, उनकी लगातार और तोखी टिप्पणियाँ यह दिखाती हैं कि वे ब्रिक्स को सिर्फ एक आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व के लिए अस्तित्व से जुड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स को “डॉलर पर हमला” बताना उनके लिए बहुत मायने रखता है, इसका मतलब है कि वे इस समूह के “डीडॉलराइजेशन” (डॉलर पर निर्भरता घटाने) के प्रयासों को सीधा खतरा मानते हैं।

इस कहानी में ट्रंप की बयानबाजी चिंताजनक है। वे बार-बार यह दावा दोहराते हैं कि “मेरी टैरिफ लगाने की धमकी के कारण सब देश ब्रिक्स से बाहर निकल गए,” जबकि सच्चाई यह

- ट्रंप जितनी धमकियां देते हैं उतना ही ब्रिक्स के घटक और अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का एकाधिकार खत्म करना चाहते हैं।
- ट्रंप ने यह भी दंभपूर्वक कहा कि जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकियां दीं ब्रिक्स की सदस्यता घटने लगी।
- उनका यह कथन पूर्णतया असत्य और काल्पनिक है। ब्रिक्स की सदस्य संख्या तो और बढ़ी है, तथा कई नए उभरते देशों ने सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर की है।
- ब्रिक्स की सफलता से आशंकित ट्रंप व अमेरिका दोनों असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, और यही ट्रंप की अनिद्रा का कारण है।

है कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। उन्होंने यह तक कहा कि “अगर मैं चुनाव नहीं जीतता, तो आपके पास डॉलर अब आपकी मुद्रा के रूप में नहीं होता।” यह बयान दिखाता है कि ट्रंप डॉलर को अपनी निजी उपलब्धि की तरह देखते हैं, मानो डॉलर की ताकत उनकी जीत पर निर्भर हो। मौद्रिक नेतृत्व का यह निजीकरण एक गहरी चिंता का संकेत

जयपुर सेशन कोर्ट में बम की सूचना से अफरातफरी मची

जयपुर, 15 अक्टूबर। बनीपाक स्थित जयपुर सेशन कोर्ट में बुधवार सुबह बम होने की सूचना से हड़कम्प मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कोर्ट परिसर में सच अभियान शुरू किया, जिसमें बम निरोध दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम ने पूरी बिल्डिंग को खाली करवाते हुए चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। पुलिस के सच अभियान

- बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने कोर्ट परिसर खाली कराके चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

पुलिस उपयुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह सेशन कोर्ट परिसर में स्थित चौथे माले की पोक्सो कोर्ट को एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगाया हुआ है। कोर्ट

रीडर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सभी टीमों मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर की कोने-कोने की जांच की। इस दौरान अतिरिक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है दिल्ली में

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत यह घोषणा की

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। क्लाउड सीडिंग, जीआरएपी और ग्रीन क्रैकर (इको फ्रेंडली पटाखे) ये आदेश भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन लक्ष्य एक ही है - दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को घोषणा की कि अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रही तो सरकार आने वाले दो से तीन दिनों में क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करेगी। यह फैसला उस दिन के बाद आया जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए, क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स-एक्यूआई) 200 के पार चला गया था।

दीवाली से एक हफ्ते पहले जीआरएपी का लागू होना इस बात का

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। अपने सहयोगी दल भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करने के एक दिन बाद, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मौजूदा सरकार के पांच मंत्रियों को फिर से टिकट मिला है। तीन बाहुबली, जिनमें अनंत कुमार सिंह भी शामिल हैं, जदयू की पहली सूची में हैं। इस सूची में चार महिला उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है।

जेडीयू को वे पांच सीटें मिल गई हैं, जिन पर पासवान दावा कर रहे थे। बताया जाता है कि जेडीयू के कब्जे वाली सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज थे।

पहली सूची में शामिल पांच मंत्री तथा उन्हें दी गई सीटें हैं - ग्रामीण विकास मंत्री ब्रवण कुमार (नालंदा), जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन), सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी (कल्याणपुर), सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी (बहादुरपुर) और मद्य निषेध मंत्री रलेश सादा (सोनबरसा)।

जेडीयू और भाजपा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 101-101

- नीतीश इस बात से परेशान व कुपित थे कि सीट शेयरिंग समझौते के तहत चिराग पासवान को वो सीटें अलॉट की गई थीं जिन पर जदयू के उम्मीदवार पिछले चुनावों में जीत कर आए थे।
- यह पांच सीटें हैं: मोरवा सोनबरसा, राजगीर, गायघाट व मटिहानी।
- गत लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान की पार्टी ने पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांचों में जीतकर आई थी, अतः इस बार चिराग सीटों के बंटवारे पर भारी दबाव बना सके थे और उन सीटों पर भी दावा ठोक दिया था जो परंपरागत रूप से जदयू की मानी जाती थीं।

सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी गई हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान ने इस बार सीट बंटवारे में कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2020 के चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था।

कम से कम पांच सीटों - मोरवा, सोनबरसा, राजगीर, गायघाट और

मटिहानी, जिन पर जेडीयू ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, के पहले चिराग पासवान के हिस्से में जाने की संभावना थी। सूत्रों के अनुसार, इसे लेकर नीतीश कुमार नाखुश थे और उन्होंने जोर दिया कि ये सीटें जेडीयू के पास रहनी चाहिए। जेडीयू ने आज इन सभी सीटों के लिये अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2020 के चुनाव में मोरवा और गायघाट सीटें आरजेडी ने जीती थीं, जबकि राजगीर और सोनबरसा पर जेडीयू का कब्जा था। मटिहानी सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह विजयी हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू जाइन कर ली थी।

रही थी। शुरुआत में योजना थी कि 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग की जाए, लेकिन मानसून के दौरान जब प्रदूषण का स्तर कम होता है, तब कृत्रिम वर्षा कराने के बिचार की आलोचना हुई। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए मानसूनी बादलों की आवश्यकता होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे की सिफारिशों के बाद यह योजना आगे बढ़ाई गई और 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच का समय तय किया गया।

क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसी विशेष सामग्रियाँ डाली जाती हैं ताकि कृत्रिम रूप से वर्षा या हिमपात कराया जा सके। इसका उपयोग पानी की कमी, कम हिमपात, या ओले और धुंध कम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में “ग्रीन” पटाखों से मनेगी दीवाली

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के त्योहार के दौरान 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक “ग्रीन” पटाखे चलाने की अनुमति दी है।

की बुधवार को अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



125M
CELEBRATING
125 MILLION CUSTOMERS

आया त्योहार हीरो पे सवार

HF-*Deluxe*
PRO

Splendor+
XTEC 2.0



पुराना एक्स-शोरूम

~~₹ 63 133~~

शुरूआती
एक्स-शोरूम कीमत

₹ 58 200[#]

GST लाभ ₹ 4 933

पुराना एक्स-शोरूम

~~₹ 80 491~~

शुरूआती
एक्स-शोरूम कीमत

₹ 74 202[#]

GST लाभ ₹ 6 289

सीमित अवधि
ऑफर

प्रतिदिन EMI
₹ 59^{\$}
से शुरू

डाउन पेमेंट
₹ 999^{\$}
से शुरू

विशेष कॉर्पोरेट ऑफर्स
₹ 2 200[~]
तक



Hero
GoodLife

पाएँ जीतने का मौका
100% केशबैक
24 कैरट सोने का सिक्का
और कई अन्य सुनिश्चित लाभ*

Additional offers on:

Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. *T&C apply. Offer available only on limited stores. *Limited period offer, T&C apply. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. *Ex-showroom price of Splendor+ and HF Deluxe in Rajasthan.

TOLL FREE
1800 266 0018

अधिकृत डीलर: जोधपुर: महेन्द्रा हीरो, रेजीडेंसी रोड, 9289922205, हिम्मत जय हीरो, जालोरी गेट, 9289922195 श्री राम हीरो, भगत की कोठी, 9289922762, जालोर: शारदा हीरो, 9289922582, सुमेरपुर: गणेश हीरो, 9289922206, नागौर: धारणिया हीरो, 9289922199, पाली: लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, 9289233932, जैसलमेर: श्री राम मोटर्स, 9289923223, बालोतरा: महेश हीरो, 9289922529, सोजत सिटी: बजरंग हीरो, 9289922840, मेड़ता सिटी: जय राना हीरो, 9289922841, सिरोंही: सिरोंही हीरो, 9289923030, एमोशिफ्ट डीलर: जोधपुर (बोकंदा): श्री महादेव मोटर्स, 9414602773, भीनमाल: हनुमान ऑटो एजेंसीज, 6376708654, मारवाड़ जंक्शन: राज मोटर्स, 9828131221, पोकरण: पोकरण मोटर्स, 9414149260, फलोदी: जनता ऑटोमोबाइल्स, 9414418357, बाड़मेर: कीर्ति मोटर्स, 9828724333, 9521721288 सांचोर: अनिल मोटर्स, 9950048742, रेवधर: शुभलक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, 9414694901, बालेसर: सांखला ऑटोमोबाइल्स, 02929-242190, 7665000343, नाडोल: धनलक्ष्मी मोटर्स, 9929290125, तिवरी: भगवती मोटर्स, 7665000358, 02926-228155, रोहट: श्री जगदम्बा एजेंसी, 9001140159, 02936-268429, चोहटन: श्री आशापूर्णा मोटर्स, 8769231111, 9636830075, शिव: श्री महालक्ष्मी मोटर्स, 9460463139, स्वरूपगंज: आशीर्वाद ऑटोज, 9460834387, भोपालगढ़: मनीष मोटर्स, 9462783469, 9414563845, बिलाड़ा: आई.जी. मोटर्स, 99672099902, 02930-222525, धनौरी कला: टाक मोटर्स, 9828975555, 9462551915, रामसिन: हितेश ऑटो, 7727989938, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) जोधपुर: हिम्मत जय हीरो 9289922195, बालोतरा: महेश हीरो, 9289922529, सिरोंही: सिरोंही हीरो, 9289923030.

राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल के खिलाफ दायर पी.आई.एल. सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शीर्ष अदालत ने कहा कि, “जयपुर की यह विवादित भूमि, वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है”

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार की दो योजनाओं राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल का निर्माण रोकने और इस जमीन को वन भूमि घोषित करने के लिए दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। सीजेआई बी.आर.गवई व जस्टिस के. विनोद चन्द्रन ने यह आदेश टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर एक पीआईएल पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि जयपुर की सांगानेर तहसील स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में इन परियोजना की जमीन वन भूमि है, और

- ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

ऐसे में इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाए।

जवाब में राज्य सरकार व रीको की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि संबंधित भूमि 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसकी वैधता

छिपाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राज्य सरकार ने परियोजना वाली जगह पर कोई पेड़ नहीं काटे हैं और केवल 56 पेड़ों को ही मंजूरी लेकर प्रत्यारोपित किया है। वहीं उनकी संख्या से 10 गुना अधिक पौधे वृक्षारोपण के तौर पर लगाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स – ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

एफएमडी नेटवर्क लेबारेट्री की समीक्षा बैठक

जयपुर। देश में पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा खुरपका मुहपका रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एफएमडी नेटवर्क लेबोरेट्री की 3२वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का दो दिवसीय आयोजन आज जयपुर में राज्य रोग निदान केंद्र, पशुपालन विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। संयुक्त निदेशक राज्य रोग निदान केंद्र डॉ. लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ।

प्रसारण निगम का नया पेंशन पोर्टल शुरू

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पेंशन पोर्टल शुरू किया है। अब पेंशन से जुड़ी जानकारी या दस्तावेजों के लिए कर्मचारियों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, व घर बैठे ही पेंशन सम्बन्धी सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट, आदेश और भुगतान की जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

एस.एम.एस. अस्पताल में रिश्वतकांड के बाद तीन पुराने कर्मचारी हटाए

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । रिश्वत कांड में पकड़े गए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉ मनीष अग्रवाल के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टोर शाखा में फेरबदल किया है।

जिसमें प्रिंसिपल ने स्टोर शाखा के तीन कर्मचारियों को वहां से हटा कर उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इसके अलावा जो कर्मचारी सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत था, उसे हटाकर स्टोर इंचार्ज बना दिया गया है। कॉलेज के आदेशों के अनुसार, स्टोर शाखा (उपापन) में कार्यरत जगदीश प्रसाद यादव को हटाकर स्टोर कीपर बनाया गया है।

वहीं केदार प्रसाद स्वर्णकार (सामान्य शाखा) और ऋषि कुमार (संस्थापन शाखा) को स्टोर शाखा (उपापन) में नियुक्त किया गया है। सुरेन्द्र कुमार पाटीदार को स्टोर शाखा (उपापन) से सामान्य शाखा में, प्रमोद सिंह को लेखा शाखा से भंडार शाखा में और धनंजय सिंह को भंडार शाखा से लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया है।

- स्टोर कीपर को हटाकर स्टोर इंचार्ज का सौंपी जिम्मेदारी

इसके अलावा, शंकर लाल जलुथरिया, जो पिछले कई सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे, शंकर लाल जलुथरिया को अब स्टोर इंचार्ज बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड में पकड़े गए डॉ मनीष अग्रवाल पर 1१ शाखाओं का भार था , वो 1१ शाखाओं का काम देखते थे। डॉ मनीष अग्रवाल के पास आईटी सेल, आरटीआई एवं लीगल सेल, महिला एवं जनाना हॉस्पिटल के सुपरविजन, पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट समेत कई अन्य विभागों का प्रभार था।बताया जा रहा है।

कि मेडिकल कॉलेज में स्टोर शाखा का महत्वपूर्ण रोल है। मेडिकल कॉलेज के अलावा इससे अटैच 7 अन्य अस्पताल में मेडिकल से जुड़े उपकरण तमाम सामान और दवाईयां सप्लाई होती है।

पंचायतीराज विभाग का अधिशाषी अभियंता रामवतार मीणा निकला करोड़ों का मालिक

ए.सी.बी. की टीमों ने ऑपरेशन “भूदेव” चलाकर रामवतार मीणा के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी और उदयपुर में एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दंड कर ऑपरेशन “भूदेव” चलाया। ए.सी.बी. ने रामवतार के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी व उदयपुर में स्थित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया।

एसीबी की सर्व कार्यवाही में करोड़ों रुपये के आलीशान मकान और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंचायती राज विभाग,इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा द्वारा पद पर रहते हुए रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां



आरोपी रामवतार मीणा

अर्जित की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रूपए है। इस शिकायत का एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तथा अधिकारी द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लॉट्स, फार्म हाउस, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुए। जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां

‘कागजों में नहीं धरातल पर काम चाहिए, स्कूलों की मरम्मत का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से भी हो’

–कार्यालय संवाददाता–

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से कराने की मंशा जताते हुए न्यायमित्र सहित सभी पक्षों को इसके लिए नाम सुझाने को कहा है। वहीं अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विद्यार्थियों की मोत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए

- राजस्थान में जर्जर स्कूलों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को विस्तृत कार्य योजना पेश करने के आदेश दिए
- अदालत ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मोत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए

जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का बजट तय किया गया है और आगामी मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शेष स्कूलों में मरम्मत का काम नवंबर, 2026 तक पूरा कर लेंगे। अदालत से कहा कि 5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी, लाखों रुपए तो रंग-सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता

है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो और बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 1१.46 फीसदी बजट स्वीकृत किया गया है। अदालत ने मरम्मत के काम के निरीक्षण का काम स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मंशा जताते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती से घटनाएं होती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी से निरीक्षण कराने के बजाए

दिवाली से पूर्व 1५9 आवंटियों को मिले सपनों के घर के आवंटन पत्र

यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्ा ने लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे ।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित

- शहरी सेवा शिविर 2025 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 2200 से ज्यादा प्रकरणों को निस्तारण किया

मण्डल के वृ्त प्रथम कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत किया गया। मंत्री खर्ा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर सर को छत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री खर्ा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव

आयकर विभाग जयपुर रेंज प्रथम का एमटीएस गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय जयपुर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग जयपुर रेंज-प्रथम एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के विष्णु पारीक को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को परिव्रादी ने शिकायत दी कि उसकी फर्म साकेत जेम्स के आयकर रिटर्न वर्ष 2014-15 के आयकर अपीलीय



अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिव्रादी के करीब 58 लाख रुपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये।

“विकसित राजस्थान 2०47” के विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी “विकसित राजस्थान 2047” विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक काम कर ही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बने इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और श्रम के विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2०47 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि आप काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही हैं। सभी जिलों की स्कूलों की ग्रैंडिंग तय हो ताकि, काम को लेकर प्राथमिकता तय हो सके। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल फोकस सुरक्षा को लेकर है। अदालत मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं स्वतंत्र संस्था से रिपेयरिंग का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराने के संबंध में सरकार से निर्देश लेने पड़ेगे। एजी ने कहा कि नवंबर माह में केन्द्र सरकार से भी पैसा जारी होगा और उन्हें रोडमप पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करते हुए सभी पक्षों को स्वतंत्र एजेंसी का नाम सुझाने को कहा है।

एक अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर मंथन

जयपुर । बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराने और पढ़ाई के दिवसों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग आगामी सत्र से एक बड़ा नवाचार करने की ओर अग्रसर है। इसके तहत विभाग अगला शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से आरंभ करने पर विचार कर रहा है। इस बाबत शिक्षा संकुल में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल के अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से नए सत्र को एक अप्रैल से शुरू करने पर मंथन किया गया। बैठक में शासन सचिव कुणाल ने इस नवाचार के उद्देश्य बताते हुए कहा कि शैक्षिक सत्र में परिवर्तन से एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण संचय होगा। इससे न केवल शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210-220 दिवस तक हो जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक समय भी मिलेगा। इसके साथ ही सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर से एकरूपता स्थापित होने से विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि की भी संभावना है।

इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कथित समस्याओं की भी ध्यान पूर्वक सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सतीश्वर जाट ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए और विभाग की ओर से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य

बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को अनुमोदित किया था। केन्द्रिय हृ गंभी अमित शाह ने भी13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान-2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1१५6 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और श्रम के विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2०47 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

ग्रामीण परिवारों को अब तक एक लाख 48 हजार पट्टे वितरित

ड्रोन के माध्यम से 35 हजार 916 गांवों का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हुआ

जयपुर, 15 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार भूमि स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीणों को पट्टे वितरित कर रही है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य के 2 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी, जिसकी पालना में अब तक लगभग 1 लाख 48 हजार 492 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द ही स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाएं। योजना के अन्तर्गत, ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से अब तक 35 हजार 916 गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, स्वामित्व कार्ड वितरण एवं सर्वेक्षण कार्यों की सतत निगरानी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

ब्रिक्स ट्रंप की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की अमेरिकी नीति पर नाराजगी जताई है। एक तरह से ट्रंप की यह झल्लाहट ब्रिक्स के आरोपों को ही सही ठहराती है। ब्रिक्स की सदस्यता को अमेरिका के प्रति शत्रुता से जोड़कर, वे पश्चिम की आर्थिक दादागिरी के उसी आख्यान को पुष्ट करते हैं, जिसका ब्रिक्स विरोध करना चाहता है। विडंबना साफ है: धमकियों के जरिए ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश में ट्रंप इसके अस्तित्व के औचित्य को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर घरेलू दशकों के लिए यह बयानबाजी ट्रंप की राजनीतिक छवि को मजबूत करती है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो अमेरिकी नैकरियों, डालर और राष्ट्रीय गर्व की रक्षा करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उनकी

गहरी असुरक्षा को दिखाती है, कि अब एकध्रुवीय (यूनीपोलर) आर्थिक व्यवस्था ढह रही है। डॉलर की “वैश्विक बादशाहत” पर उनका बार-बार जोर देना बीते गौरव के प्रति एक तरह की लालसा जैसा लगता है। ट्रंप का बार-बार यह दोहराना केवल बयानबाजी का अतिरेक नहीं है। यह बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरणों को लेकर उनके भीतर की बेचैनी का संकेत है, जहाँ अब आर्थिक ताकत बंट रही है और डॉलर का एकछत्र शासन कमजोर हो रहा है। उनकी यह रक्षात्मक भाषा यह स्पष्ट करती है कि वे ब्रिक्स को केवल एक प्रतिस्पर्धी समूह नहीं, बल्कि उस नए वैश्विक संतुलन के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो उन्हें और शायद अमेरिका को बेहद असहज बनाता है।

मृत्युदंड के लिए ज़हर के इंजेक्शन का विकल्प सरकार ने ठुकराया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मृत्युदंड की सजा के तरीके को बदलने की अपील की गई है, लेकिन केन्द्र सरकार इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि दोषी को फांसी या जहर का इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि, केन्द्र ने हलफनामे दायर कर कहा कि ऐसा करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।” इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि केन्द्र समय के साथ विकसित होने को तैयार नहीं दिख रहा है। केन्द्र की ओर से वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि समस्या यह है कि सरकार बदलने को

■ सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी की सरकार बदलने को तैयार नहीं है।

तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी प्रक्रिया है, समय के साथ चीजें बदल गई हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि फांसी की जगह मौत की सजा जहर का इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर से दी जा सकती है, इन तरीकों से सजायाफता की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है। यह जनहित याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है। इसमें फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताया गया है। याचिकाकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के तहत “फांसी देकर मृत्युदंड देने को असंवैधानिक” घोषित

भजन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। मिश्रा 19 अगस्त 2025 को जनसुराज छोड़कर भाजपा में शामिल हुये थे। सूची के अनुसार, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं, मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदार नाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा (सुरक्षित) से वीरेन्द्र कुमार, बाढ़ से डा. सियाराम सिंह , अगिआंव (सुरक्षित) से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है।

वांगचुक की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) देरी को हिरासत को चुनौती देने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और जोधपुर सेंट्रल जेल के पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा था, जब अदालत ने अंगमो की ओर से

पाक व अफगानिस्तान में सीज़ फायर

काबुल/ इस्लामाबाद, 15 अक्टूबर। एकदूसरे के खून के प्यासे बने पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के संघर्षविराम पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये संघर्षविराम बुधवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया। इससे पहले, दोनों की लड़ाई सीमा पर सैन्य ठिकानों

■ पिछले हफ्ते से चल रही भारी गोलाबारी के बाद 48 घंटे की शांति रहने की संभावना है।

पर हमले से आगे बढ़ कर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई रिहाइशी इलाकों पर हमले किए और काबुल व कंधार में एयरस्ट्राइक कर दी।

ये जंग पिछले हफ्ते उस समय तेज हो गई थी, जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कैपों को निशाना बनाते हुए सीमा पार से हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान अफगान तालिबान पर टीटीपी आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगा रहा है, जो 2021 से सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।

अंता उपचुनाव में जनता सरकार को आईना दिखायेगी- पायलट

टोंक, 15 अक्टूबर (निसं)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रनिंग ट्रैक पर सिंथेटिक पी.यू. फ्लोरिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मीडिया के साथियों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि अंता में उपचुनाव क्यों हो रहा है। माननीय उच्च

■ उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इस प्रकार का आधुनिक रनिंग ट्रैक बहुत कम जगह देखने को मिलता है।

पायलट ने टोंक में रनिंग ट्रैक पर सिंथेटिक फ्लोरिंग निर्माण का लोकार्पण किया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में रनिंग ट्रैक पर सिंथेटिक पी.यू. फ्लोरिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

अनेक जगह देखा गया है कि अनेक बच्चे एवं नौजवान नशे की लत में पड़ जाते हैं। नशे की लत ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका हम सभी को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। इसी को ध्यान

में रखते हुए हमने मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम, रनिंग ट्रैक का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि नौजवान अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकें।

जदयू ने भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पैदा कर दिया है। उनका मानना है कि उनकी वरिष्ठ पार्टनर भाजपा गठबंधन में उनकी भूमिका को कम करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू के सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव परिणामों के बाद सभी विकल्प खुले रहेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, चुनाव बाद कोई भी फैसला बिहार के हित और पार्टी की दीर्घकालिक मजबूती को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि अगर भाजपा के साथ रिश्ते और बिगड़ते हैं तो नए गठबंधन

की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच, दिल्ली और पटना में नीति अपनाए हुए हैं, तथा उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव नतीजों तक स्थिति संभल जाएगी। लेकिन जेडीयू की यह ताजा चुनौती बताती है कि गठबंधन अब आपसी अविश्वास और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता के माहौल में बिहार चुनाव में उतर रहा है। यह उस गठबंधन के लिए असहज स्थिति है, जो लगभग दो दशकों से राज्य पर शासन कर रहा है।

श्रीलंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अमरसूर्या शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ-साथ नीति आयोग का भी दौरा करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा रही श्रीलंका की प्रधानमंत्री अपने संस्थान का भी दौरा करेंगी।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भी कहा कि जब प्रतिबंध लगाया गया था, तब कोविड-19 के दौरान को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत अधिक अंतर नहीं आया था। पीठ ने कहा, अर्जुन गोपाल मामले में आए फैसले के बाद ग्रीन पटाखों की अवधारणा शुरू की गई थी। पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने उत्सर्जन में काफी कमी की है। पीठ ने आदेश दिया कि ग्रीन पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही फोड़े जा सकते हैं। पीठ ने पटाखे फोड़ने के लिए सुबह छह बजे से सात बजे के तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर को संकेत दिया था कि वह दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है लेकिन एक निश्चित समयावधि के साथ। अदालत ने उस दिन कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध “न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श” क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है और न्यायसंगत संतुलन की आवश्यकता है।

वायु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया विमानों, रॉकेटों या जमीनी मशीनों के माध्यम से की जा सकती है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस मिश्रण में सिल्वर आयोडाइड नैनोकण, आयोडीन युक्त नमक और चट्टानी नमक (रॉक सॉल्ट) शामिल हैं।

जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हुई

जोधपुर, 15 अक्टूबर (कासं)। जैसलमेर में हुए निजी स्लीपर बस अग्निकांड हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। हादसे में झुलसे दस साल के यूसुस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार, अब भी चार मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच हादसे में मृत लोगों के परिजनों की डीएनए जांच के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में सैपलिंग शुरू हो गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 24 घंटे के बाद सभी की रिपोर्ट आ जाएगी। महात्मा गांधी अस्पताल में 10 शव लाए गए, एम्स की मोर्चों में रखे गए। वहां भी सैपलिंग हो रही है। सैपल कलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी पर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वैरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि कोई गलती न हो। उन्होंने बताया अधिकतम 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले डीएनए की सैपलिंग शुरू होने से पहले परिजनों का

अभी चार मरीज वेंटिलेटर पर, मृत यात्रियों के परिजनों की डीएनए जांच की सैपलिंग शुरू

■ हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेन्द्र चौहान के भाई ने बस मालिक व ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन और पुलिस ने फोन कर सुबह 6 बजे महात्मा गांधी अस्पताल बुलाया, लेकिन यहां घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। हादसे में जान गंवाने वाले एक मृतक के भाई ने कहा कि हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में हो रही डीएनए सैपलिंग की व्यवस्था देखने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक मामला ऐसा है, जिसमें मृतक की बूढ़ी मां फलोदी जिले में रहती है। वह यहां नहीं आ सकती। इसके लिए फलोदी जिला प्रशासन से संपर्क कर उनका सैपल

कलेक्ट करवाया जा रहा है। सभी घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगाई गई है। मंगलवार रात करीब 12 बजे से आज सुबह 5 बजे तक 19 शवों से कुल 21 बोन सैम्पल लिए गए और परिजनों के डीएनए सैम्पल लिए गए। बुधवार सुबह तक करीब 10 परिजनों के सैम्पल लिए गए। जिन्हें जोधपुर लैब भेज दिया गया, ताकि डीएनए मैचिंग के बाद शव परिजनों को सौंपे जा सकें। अस्पताल अधीक्षक डॉ। फतेहसिंह भाटी ने बताया कि यहां भर्ती मरीजों में आठ मरीजों की हालत बहुत गंभीर है, जिनको लेकर कुछ नहीं कहा

जा सकता। वर्तमान में चार मरीज ऐसे हैं, जिनको हम जल्द छुटी देकर घर भेज सकते हैं।

हादसे के बाद, मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे के शिकार पत्रकार राजेन्द्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है। बता दें कि जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे में 19 यात्रियों की मौत पर ही मौत हो गई थी, जबकि जोधपुर में उध्चार के दौरान 79 वर्षीय हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान निक्सी जवांघ ने दम तोड़ दिया। वहीं, बुधवार सुबह 10 वर्षीय यूसुस की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से डीएनए सैम्पलिंग की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है।



FLAT 50% OFF

ON MAKING CHARGES* FOR PREMIUM GOLD – JEWELLERY –

KALYAN SPECIAL 1g GOLD RATE ₹11795 | SAVE ₹325 1g | MARKET 1g GOLD RATE ₹12120

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: TONK ROAD - PH: 96025 33433. VAISHALI NAGAR - PH: 91158 03333 | UDAIPUR - PH: 88756 78133 | JODHPUR - PH: 94133 12103
KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933 | SRI GANGANAGAR - PH: 74249 65433 | AJMER - PH: 77424 13156

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON @KJ BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET